

प्रेषक

डा० राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून दिनांक: 30 जनवरी, 2009

विषय:- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 5ख1/34443/जीर्ण-शीर्ण/2008-09; दिनांक: 05 दिसंबर, 2008 के संबंध में तथा शासनादेश संख्या: 1747/XXIV-3/07/02(125)06; दिनांक: 16 जनवरी, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित 03 (तीन) राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु स्तम्भ-04 पर अनुमोदित लागत के सापेक्ष स्तम्भ-5 पर पूर्व में स्वीकृत धनराशि को समयोजित करते हुए स्तम्भ-6 में अंकित विवरणानुसार कुल रू० 107.40 लाख (रुपये एक करोड़ सात लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्रश्नगत योजना में शासनादेश संख्या 657/XXIV-3/08/02(37)2008; दिनांक: 16 अप्रैल, 2008 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू० 1500.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	विद्यालय का नाम	निर्माण एजन्सी का नाम	अनुमोदित लागत	अब तक स्वीकृत धनराशि	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6
01	रा०इ०का०, बाराकूना अल्मोड़ा	ग्रा०अ०से०, अल्मोड़ा	60.70	23.70	37.00
02	रा०इ०का०, महतगांव, अल्मोड़ा	-तदैव-	30.40	10.00	20.40
03	रा०इ०का०, कांसखेत, पौड़ी	उ०प्र०रा०नि०नि०, लि० पौड़ी	82.78	32.78	50.00
		योग-	173.88	66.48	107.40

- (1)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

अभि

क्रमशः.....2

(2)

- (2)– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
 - (3)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
 - (4)– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेकअप किया जाये।
 - (5)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मददे नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
 - (6)– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च-अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल पर आवश्यकतानुसार एवं प्राप्त निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
 - (7)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
 - (8)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाये।
 - (9)– जी०पी०डब्ल्यू फार्म 9 शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य का पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।
 - (10)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 2047/XIV-219(2006), दिनांक: 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित कराते समय कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
 - (11)– निर्माण कार्य की गुणवत्ता के लिए सम्बन्धित निर्माण ऐंजेन्सी उत्तरदायी होगी।
 - (12)– कार्यों की समयबद्धता के साथ वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण करना तथा भवन विभाग को हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय, विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 2– उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहां आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन एवं महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

(3)

3.- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या: 11 के अधीन लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेल-कूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-202-माध्यमिक शिक्षा-00-आयोजनागत-11-राजकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के भवनहीन/जीर्ण-शीर्ण भवनों का निर्माण- 24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा.

4.- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 682 (P)/वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3/2008 दिनांक: 20 जनवरी, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(डा० राकेश कुमार)
सचिव

संख्या: 2354(1)/XXIV-3/08/02(125)2006; तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा० मुख्य मंत्री जी।
- 3- निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री जी।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- आयुक्त, कुमायूँ मण्डल- नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 6- अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल- नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- जिलाधिकारी, अल्मोड़ा एवं पौड़ी।
- 8- कोषाधिकारी, अल्मोड़ा एवं पौड़ी।
- 9- जिला शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा एवं पौड़ी।
- 10- बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
- 11- वित्त विभाग अनु०-03/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 12- कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
- 13✓ एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 14- संबंधित निर्माण एजेन्सी।
- 15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी०एल०शाह)
उप सचिव।